

सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (अंग्रेजी: यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए लाभकारी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना थी। [१]: ११ अप्रैल १९९९ से, ईएएस एक आवंटन बन गया। आधारित योजना। [१]: ३ यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किया गया था। Sampoorna ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को रोजगार आश्वासन योजना (EAS) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) के प्रावधानों को मिलाकर लॉन्च की गई थी। कार्यक्रम प्रकृति में स्व-लक्ष्यीकरण है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को रोजगार और भोजन प्रदान करना है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। मूल सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वास्तव में रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के तहत प्रावधानों का एक संयोजन है। [२]: Gr० ९ अक्टूबर 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का पुनर्गठन और नामकरण किया गया और यह अप्रैल 1981 से एक नियमित कार्यक्रम बन गया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नियोजित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का कार्यान्वयन है। केंद्र-राज्य का योगदान 50:50 अनुपात के आधार पर था। 1989 में NREP को जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। [3] प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर 1 अप्रैल, 1989 को जवाहर रोजगार योजना (JRY) शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का शहरी संस्करण नेहरू रोजगार योजना थी। यह पिछले रोजगार कार्यक्रमों का एक समेकन था और यह उस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम था, जिसमें विशेष रूप से पिछड़े जिलों में प्रति व्यक्ति 90-100 दिन रोजगार देने का एक सामान्य उद्देश्य था। गरीबी रेखा से नीचे के लोग मुख्य लक्ष्य थे। योजना ग्रामीण स्तर पर लागू की गई थी। प्रत्येक गाँव को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कवर किया जाना था। गाँव को जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का सहयोगी और समर्थन मिला। 80:20 अनुपात में केंद्रीय और राज्य द्वारा व्यय का जन्म हुआ। 1993-94 के बाद से इस योजना को और अधिक लक्ष्य उन्मुख बनाया गया और बजटीय आवंटन में वृद्धि के माध्यम से इसका विस्तार किया गया। इसे 3 धाराओं में विभाजित किया गया था। फर्स्ट स्ट्रीम: JRY के तहत सामान्य कार्यों की तुलना करना और दो उप-योजनाएँ इंदिरा आवास योजना और मिलियन वेल्स योजना। इस धारा को कुल आवंटन का 75% मिला।

नई दिल्ली आवास योजना में इस अवधि के दौरान आवंटन को 6% से बढ़ाकर 10% और मिलियन वेल्स योजना में 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया। दूसरी धारा: इसे तीव्र JRY भी कहा जाता था और इसे चयनित 120 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। इसे 20% आवंटन मिला। थर्ड स्ट्रीम: इनोवेटिव कार्यक्रमों के लिए इसे 5% आवंटन के साथ छोड़ दिया गया था जिसमें श्रम पलायन की रोकथाम, सूखा प्रूफिंग वाटरशेड आदि कार्यक्रम शामिल थे। [4] 1 अप्रैल, 1999 से इस योजना का स्थान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ने ले लिया। बाद में 25 सितंबर, 2001 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। [3] [५] जवाहर ग्राम स्मृति योजना जवाहर ग्राम स्मृति योजना, जिसका नाम भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, जिसका उद्देश्य एक ज़रूरत आधारित ग्रामीण बुनियादी ढाँचा तैयार करना था। [१]: १ इन दोनों कार्यक्रमों ने ग्रामीण गरीबी को कम करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। [१: १] २००१ में। द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को मजदूरी रोजगार और खाद्य अनाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था। [१]: १ इस योजना को पहले जवाहर रोजगार योजना (JRY) के नाम से जाना जाता था, जिसे 1989 में दो वेतन रोजगार कार्यक्रमों: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) के विलय के द्वारा शुरू किया गया था। [1]: 6 यह एकल था। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से लागू सबसे बड़ा वेतन रोजगार कार्यक्रम। [१]: ६ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) 15 अगस्त 1983 को भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया था। जबकि इसके अंतर्गत अधिकांश उद्देश्य और वजीफा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) के समान थे, यह केवल भूमिहीन तक सीमित होना था, जिसमें 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध था। इसके अलावा, कुछ गतिविधियों के लिए विशेष रूप से धनराशि निर्धारित की गई थी- सामाजिक वानिकी के लिए 25 प्रतिशत, केवल अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के लिए 10 प्रतिशत और इंदिरा आवास योजना के तहत आवास के लिए 20 प्रतिशत। सातवीं योजना में, रु .२२१ करोड़ खर्च किए गए और ११५ करोड़ मानव दिवस प्रति दिन २.०० करोड़ रुपये के औसत व्यय के साथ उत्पन्न किए गए। सामाजिक वानिकी पर केवल 16 प्रतिशत खर्च किया गया था, लेकिन आवास पर 22 प्रतिशत खर्च किया गया था, - एससी / एसटी के लिए बनाए गए पांच लाख से अधिक घरों के साथ और बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया। अन्य निर्माण, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण आदि में ग्रामीण सड़कों का हिस्सा 22 प्रतिशत था, प्रत्येक का एक छोटा हिस्सा

था।

1989 में इस कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। [३] रोजगार आश्वासन योजना ईएस को पहली बार 2 अक्टूबर 1993 को देश के किसी न किसी, बीहड़, कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित 1778 ब्लॉकों में लागू किया गया था। [1]: 3 SGRY की घोषणा अंत में, 15 अगस्त 2001 को, तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नए वेतन रोजगार कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की। [१]: १ योजना २५११ २००१ को शुरू की गई थी। [१]: १ [२] : 709 प्रावधान इस योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बच्चों के माता-पिता के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो खतरनाक व्यवसायों से हट जाते हैं। [२]: 2० ९ जबकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी इसके तहत पात्र हैं। । योजना [2]: 709 रुपये का बजट। योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें 50 लाख टन अनाज का प्रावधान शामिल है। [2]: Again० ९ फिर से निवेश investment५-२५ अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया गया है। [२]: Food१० खाद्यान्न। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती है, लेकिन परिवहन की लागत राज्यों द्वारा वहन की जानी चाहिए। [२]: provided१० इस तथ्य के बावजूद कि ईएस और जेजीएसवाई एकीकृत थे, ईएस और जेजीएसवाई के लिए वर्ष 2001-02 के लिए अलग से धन आवंटित किया गया था। [1]: 3 यह कार्यान्वयन और लेखांकन की सुविधा के लिए किया गया था। [१]: ३ हालाँकि, से। वित्तीय वर्ष २००२-०३ के बाद से, एकीकृत बजट ईएस और जेजीएसवाई दोनों के लिए अपनाया गया था। [१]: ३ कार्यान्वयन कार्यक्रम जिला पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। [२]: allocated१० संसाधनों को २०-३०-५० अनुपात में आवंटित किया जाता है। [२]: the१० ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर अपना काम शुरू करती हैं। [२]: ग्राम पंचायतों के लिए the१० ५० प्रतिशत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। [२]: 22१० २२ प्रतिशत जिला और मध्यवर्ती पंचायतों को आवंटित धन का उपयोग SC / ST समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के विकास के लिए भी किया जाता है। [२]: District१० इस योजना के तहत ठेकेदारों या बिचौलियों के रोजगार की अनुमति नहीं है। हालाँकि, इस योजना को NREGP में शामिल किया गया था जिसे 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया है।